RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 24 JUNE TO 30 JUNE 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 44 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

तेल रिफाइनरियों की कार्य क्षमता में सुधार Page 2

रेलवे ने वेंडरों के लिए नियमों को आसान बनाया Page 4

ऑडी ने 'आरएस-7 स्पोर्टबैक' कार की बुकिंग शुरू की, - अगस्त से करेगी डिलिवरी Page 7

editoria!

कोल सेक्टरः काले हीरे पर नजर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के 41 कोल ब्लॉक में कमर्शल माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करते हुए इसे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पहले ही की गई घोषणाओं में यह फैसला भी शामिल था। याद रहे, पिछले कुछ सालों में कोल सेक्टर भयानक ठहराव से गुजरा है। 1993 से 2010 के बीच हुई कुल 218 नीलामियों में सिर्फ 4 को छोड़कर बाकी सभी 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई थीं। इसके छह साल बाद नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के क्रम में प्रधानमंत्री ने पुराने मामलों में उलझने के बजाय इस बात पर हैरत जताई कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार होने के बावजूद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक देश क्यों है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार कोयले का खनन और खपत बढ़ाने की राह में मौजूद सारी मुश्किलें दूर करने का मन बना चुकी है। इधर काफी समय से इस क्षेत्र में संभावनाएं कम ही होती दिखी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत दुनिया में पर्यावरण के सवाल पर बढ़ती जागरूकता के चलते कोल माइंस और थर्मल पावर प्लांट्स के खिलाफ बने माहौल की है। विश्व बैंक 2015 में ही ऐसी इकाइयों को फंड न देने का ऐलान कर चुका है। एक दिक्कत भारतीय कोयले की क्वॉलिटी से भी जुड़ी है जिसमें राख ज्यादा निकलती है और जिसकी प्रति इकाई ऊर्जा उत्पादन क्षमता कम है। तीसरी बड़ी दिक्कत यह है कि भारत के ज्यादातर कोयला भंडार घने जंगलों या आबादी वाले इलाकों में हैं, जिससे खनन शुरू होने के पहले ही परियोजना विवादग्रस्त हो जाती है। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में सुधार लागू करने और स्थानीय आबादी के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ने की बात कही है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार ने सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी कार्ययोजना तैयार की है। कोल सेक्टर को लेकर पिछले दिनों उठे विवादों को एक तरफ रख दें तो यह बात भी ध्यान रखने की है कि कई कंपनियों ने कोल ब्लॉक खरीदने के कई साल गुजर जाने के बाद भी माइनिंग शुरू नहीं की थी। इसके पीछे उनका दूसरी परियोजनाओं में व्यस्त होना भी एक कारण हो सकता है लेकिन धंधे में पर्याप्त मुनाफे की उम्मीद न होना इसकी बड़ी वजह बताई जाती रही है। बहरहाल, यह सबके हित में है कि कोल सेक्टर के पुनरुद्धार की जितनी भी संभावना हो उसे आगे बढ़ाया जाए। अगर देश कोयले के उत्पादन के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में भी कामयाब होता है, साथ ही पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं का भी पूरा ध्यान रखा जाता है तो न सिर्फ आत्मनिर्भरता की दृष्टि से यह एक बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को इससे उम्मीद की वह रोशनी भी मिलेगी, जिसकी उसे आज सबसे ज्यादा जरूरत है।

लगातार 18वीं मूल्यवृद्धि के बाद दिल्ली में पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल

आईपीटी नेटवर्क

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहली बार डीजल का दाम पेट्रोल से अधिक हो गया है। बुधवार को कीमतों में लगातार 18वीं बढ़ोतरी के बाद अब डीजल और पेट्रोल का दाम लगभग बराबर हो गया है। सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की मूल्य के संबंध में अधिसूचना के अनुसार 17 दिन लगातार वृद्धि के बाद बुधवार को पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। वहीं डीजल कीमतों में देशभर में 48 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब डीजल का दाम 79.88 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल की कीमत 79.76 रुपये प्रति लीटर है। मूल्यवर्धित कर (वैट) की वजह से विभिन्न राज्यों में वाहन ईंधन के दाम अलग-अलग होते हैं। हालांकि, सिर्फ दिल्ली में ही डीजल का दाम पेट्रोल से अधिक है। राज्य सरकार ने पिछले महीने इसपर बिक्रीकर या वैट में बड़ी वृद्धि की थी। मुंबई में पेट्रोल 86.54 रुपये प्रति लीटर है। वहीं डीजल 78.22 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 83.04 रुपये प्रति लीटर और डीजल 77.17 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 81.45 रुपये प्रति लीटर और डीजल 75.06 रुपये प्रति लीटर है। बेंगलुरु में पेट्रोल 82.35 रुपये और डीजल 75.96 रुपये प्रति लीटर है। इसी तरह हैदराबाद में पेट्रोल 82.79 रुपये प्रति लीटर और डीजल 78.06 रुपये प्रति लीटर है। सामान्य तौर पर कम कर की वजह से डीजल का दाम पेट्रोल से 18 से 20 रुपये प्रति लीटर कम रहता है। लेकिन हाल के वर्षों में डीजल पर कर बढ़ने की वजह से यह अंतर कम होता जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने पांच मई को डीजल पर वैट की दर 16.75 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी थी। इसी तरह पेट्रोल पर कर की दर को 27 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया था। चूंकि यह शुल्क मूल्यानुसार लगता है ऐसे में प्रत्येक बार पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा कीमतों में वृद्धि से इसका वास्तविक प्रभाव बढ़ता जाता है। उल्लेखनीय है कि सात जून से पेट्रोलयम विपणन कंपनियों ने बुधवार तक लगातार 18 दिन डीजल कीमतों में बढ़ोतरी की है। इसी तरह पेट्रोल के दाम लगातार 17 दिन बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 82 दिन तक कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। 18 दिन में डीजल कीमतों में 10.49 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 17 दिन में पेट्रोल 8.5 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है।

कोरोना वायरस संक्रमण

ओएनजीसी ने अरब सागर में दो तेल रिग बंद किए

एजेंसी

नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी ने 54 कर्मचारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने और एक कर्मचारी की मौत के बाद अरब सागर स्थित अपने दो तेल रिगों में अस्थाई रूप से परिचालन बंद कर दिया है, हालांकि इससे तेल और गैस का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। तेल रिग एक बड़ी मशीन है, जिसका इस्तेमाल धरती में गहरा छेद करने के लिए किया जाता है, ताकि तेल निकाला जा सके। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आने के बाद कंपनी की प्रमुख तेल फील्ड मुंबई हाई और पश्चिमी तट में स्थिति बसई में दो रिगों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। इन रिगों को बंद करने से उत्पादन प्रभावित नहीं होगा और कंपनी मुंबई हाई से 1,70,000 बैरल प्रति दिन (बीपीडी) कच्चा तेल और 12 मीट्रिक मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) गैस का उत्पादन जारी रखेगी। इसी तरह बसई से 60,000 बीपीडी तेल और 32 एमएमएससीएमडी गैस का उत्पादन जारी रहेगा। मुंबई हाई और बसई भारत के प्रमुख तेल और गैस उत्पादक क्षेत्र हैं, जिनका देश के उत्पादन में लगभग दो-तिहाई हिस्सा है। ओएनजीसी ने एक बयान में कहा, ''हमारी सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं। उत्पादन स्तर बनाए रखा जा रहा है। कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां बरती जा रही हैं।'' अधिकारियों ने कहा कि कंपनी कर्मचारियों की जांच के लिए सख्त नियमों का पालन कर रही है और कोई हल्का सा लक्षण होने पर भी उनकी देखरेख की जा रही है।

डॉलर के मुकाबले रुपया छह पैसे गिर कर 75.72 पर बंद

आईपीटी नेटवर्क

मुंबई। घरेलू शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच अंतरबैंक विदेशी विनिमय बाजारमें रुपया बुधवार को डालर के मुकाबले आरंभिक लाभ बरकार नहीं रख सका और अमेरिकी मुद्रा के समक्ष छह पैसे की गिरावट दर्शाता 75.72 पर बंद हुआ। बाजार सूत्रों के अनुसार कमजोर घरेलू शेयर बाजार, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप तथा भारत-चीन सीमा पर तनाव जैसी घटनाओं से निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो रहा है।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 75.61 पर खुला। कारोबार के दौरान आरंभिक तेजी लुप्त हो गई। अंत में रुपये की विनिमय दर डॉलर के मुकाबले छह पैसे की गिरावट दर्शाता 75.72 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई। कोरोबार के दौरान डालर 75.59-75.76 रुपये के दायरे में था।मंगलवार को डॉलर-रुपया विनियम दर 75.66 पर बंद हुई थी। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 226.71 अंकों की गिरावट दर्शाता 35,203.72 अंक पर बंद हुआ।

चीन से होने वाले आयात पर हर तरफ से वार, सख्त मूड में दिख रही केंद्र सरकार

एजेंसी

नई दिल्ली। मोदी सरकार देश में चीनी माल की डंपिंग को रोकने के लिए सख्त मूड में दिख रही है। चीन सहित तीन देशों से स्टील आयात पर सरकार ने 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। इसी तरह, चीन से आने वाले सोलर आइटम पर अगस्त से 20 फीसदी की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने की तैयारी की जा रही है। यही नहीं, चीन से आने वाला माल 22 जून से बंदरगाहों पर रोक लिया गया है।

गौरतलब है कि चीन से सीमा पर हिंसक झड़प में हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए हैं। ऐसे में देश में चीन के खिलाफ जबरदस्त माहौल है और चीनी माल के बहिष्कार का अभियान चल पड़ा है। ऐसे में सरकार भी सख्ती दिखाकर कारोबार के रास्ते चीन की नकेल कसना चाहती है।

राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से आने वाले फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पादों अल्युमिनियम या जिंक के अलॉय से प्लेटेड या कोटेड पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। यह ड्यूटी अगले पांच साल तक रहेगी। जाहिर है कि इसमें निशाना चीन ही है और सरकार वहां से होने वाली स्टील के भारत में डंपिंग को रोकना चाहती है। यह एंटी डंपिंग ड्यूटी 13.07 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से 173.07 डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक होगी। यह तीनों देशों के लिए अलग-अलग होगी।

सोलर आइटम आयात पर सख्ती

इसके अलावा भारत सरकार चीन से आने वाले सोलर मॉड्यूल्स, सोलर सेल्स और सोलर इनवर्टर पर अगस्त से 20 फीसदी की बेसिक काउंटर ड्यूटी लगाने की तैयारी कर रही है, ताकि इनका चीन से आयात हतोत्साहित किया जा सके।

अभी चीन से आने वाले सोलर इक्विपमेंट पर 15 फीसदी का सेफगार्ड ड्यूटी लगता है। देश में बिकने वाले सोलर आइटम्स का 80 से 90 फीसदी हिस्सा चीन से आयात किया जाता है। भारत सरकार ने साल 2022 तक देश में 100 गीगावॉट सोलर एनर्जी पैदा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2019-20 के पहले नौ महीने में भारत ने कुल 1.5 अरब डॉलर के सोलर इक्विपमेंट का आयात किया था, जिसमें से 1.2 अरब डॉलर का आयात चीन से ही हुआ था।

बंदरगाहों पर रोके गए चीनी माल

देश में चीनी सामान के बहिष्कार का असर अब बंदरगाहों पर दिखने लगा है। आयातकों का कहना है कि सरकार ने चीन से आने वाले सामान को 22 जून से ही बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर रोक रखा है और इनकी क्लियरिंग रोक दी गई है। हालांकि इस बारे में कोई सरकारी आदेश नहीं जारी हुआ है। लेकिन कारोबारियों का कहना है कि सरकार का यह साफ संदेश है कि अगले आदेश तक चीन से आने वाले माल की डिलीवरी न की जाए।

एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के फोरम कोऑर्डिनेटर और हिंदुस्तान सीरींज्स के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव नाथ बताते हैं कि चीन से आने वाले माल की 100 फीसदी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, 'हमें यह बताया गया है कि चीन से आने वाले माल की बंदरगाहों पर 100 फीसदी जांच होगी।

खाद्य तेल की बिना-पैकिंग बिक्री पर प्रतिबंध से मिलावट पर रोक लगेगी: एसईए

एजेंसी

नयी दिल्ली। तेल उद्योग के प्रमुख संगठन, साल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) ने कहा कि देश में खुले खाद्यतेल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना ही इसमें मिलावट के खतरे को दूर करने का एकमात्र उपाय है। एसईए का यह बयान सरसों के मामले में ऐसे ही मुद्दे की जांच के लिए एक सरकारी पैनल के बनाये जाने के बीच आया है। खाद्य तेल क्षेत्र से किसी भी प्रतिनिधित्व के बिना सरकारी समिति, सरसों के तेल में कथित मिलावट के मामले पर गौर करेगी और एक महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कमेटी ने अपने सदस्यों को लिखे पत्र में यह जानकारी दी है।

सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने कहा, 'भारत में खुले तेल की बिक्री पर वर्षों पहले प्रतिबंध का नियम बना है, लेकिन किसी न किसी कारण से, कानून को कभी लागू नहीं किया गया है।' उन्होंने कहा, 'खुले तेलों की बिक्री पर प्रतिबंध के कड़ाई से कार्यान्वयन से मिलावट की समस्या से बहुत आसानी से निपटा जा सकता है। लेकिन, किसी भी तरह, वर्षों से, प्रतिबंध लागू करने के संदर्भ में छूट अवधि का बार बार विस्तार किया गया है और कार्यान्वयन केवल कागज पर ही रह गया है।' चतुर्वेदी ने कहा कि कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इसका कारण यह बताया गया है कि खुले तेल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से भारत के गरीबों को नुकसान होगा।

उन्होंने कहा, 'यह एक गलती है जिसके बारे में काफी समय से बात की जाती रही है और इसने भारत के गरीबों को लाभ के बजाय कहीं अधिक अधिक नुकसान पहुंचाया है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे गरीबों को धोखा दिया जाए और उनके स्वास्थ्य के साथ समझौता किया जाए। यह बेकार का तर्क है और इस तर्क को यथोचित रूप से इसे खारिज किया जाये।' उन्होंने कहा कि भारत में खाद्यतेल पैकेजिंग की लागत भी काफी कम है तथा उपभोक्ताओं को वैज्ञानिक रूप से पैक्ड तेल पहुंचाने के लिए 3-4 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत आती है। मिलावट की समस्या को दूर करने के लिए, एसईए अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि सभी प्रकार की बिक्री, चाहे वह पैकबंद हो या खुले तेल के रूप में की जा रही हो, वह पंजीकृत डीलरों के बीच ही हो।

खाद्य तेलों में सम्मिश्रण (ब्लेंडिंग) तथा उसमें मिलावट के बीच अंतर होने की बात कहते हुए एसईए ने कहा कि तेलों में सम्मिश्रण के कारण को एफएसएसएआई और एगमार्क जैसे नियामक निकायों द्वारा अनुमति दी गई है जिन्होंने उत्पाद के साथ-साथ लेबलिंग आवश्यकताओं के लिए भी सख्त मानक निर्धारित किए हैं। मिश्रित खाद्य तेल महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह कई पोषण और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशानिर्देश भी अधिकतम पोषण लाभ के लिए तेल में सम्मिश्रण किये लाने का समर्थन करते हैं। एसईए के अनुसार, दूसरी ओर, मिलावट, बेईमान कारोबारियों द्वारा की गई गैर कानूनी गतिविधि है। इसने कहा है, 'सरसों तेल एक महंगा तेल है, इसलिए अतिरिक्त धन कमाने के लिए कम कीमत के मिश्रण वाले विकल्पों को इस तेल में मिलाया जा सकता है।

केन्द्र ने छिलका उतरे नारियल के एमएसपी को 5.02 प्रतिशत बढ़ाकर 2,700 रुपये क्विन्टल किया

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्र ने वर्ष 2020 के सत्र के लिए, बुधवार को पके और छिलका उतरे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5.02 प्रतिशत बढ़ाकर 2,700 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। यह पहल छोटे किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई है।

पिछले सत्र के दौरान छिलका उतरे नारियल का एमएसपी 2,571 रुपये प्रति क्विंटल था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बयान में कहा, "पके और छिलका उतरे नारियल के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी से नारियल की खरीद सुगम हो सकेगी। इससे एमएसपी का लाभ लाखों छोटे किसानों तक पहुंचेगा।"

उन्होंने कहा कि हालांकि, वर्ष 2020 फसल सत्र के लिए नारियल गरी के मिलिंग के लिए एमएसपी 9,960 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन छिलका अलग किये गये नारियल के लिए उच्च एमएसपी की घोषणा से छोटे किसानों को तत्काल नकदी सुनिश्चित होती है, जो अपने उत्पाद को अपने पास रखने में असमर्थ हैं और जिनके पास नारियल गरी (कोपरा) बनाने की अपर्याप्त सुविधा है। उन्होंने कहा, "इससे उन नारियल किसानों के लिए राहत होगी जो पहले से ही महामारी और इसके कारण आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न व्यवधान के कारण प्रभावित हुए हैं।" मंत्री ने कहा, नारियल एक छोटे भूमि धारक की फसल है, इसलिए इनका एकत्रीकरण और किसान के स्तर पर खोपरा बनाने की व्यवस्था करना आम बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे देश में सभी प्रकार की फसलों को उगाने वाले किसानों के हितों को अत्यधिक महत्व दिया है।

तेल रिफाइनरियों की कार्य क्षमता में सुधार, वहीं रिलायंस ने तीसरे माह प्रसंस्करण में की कटौती

एजेंसी

नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधन कंपनी इंडियन आयल की रिफाइनरियों ने मई माह के दौरान औसतन 77 प्रतिशत की परिचालन क्षमता के साथ काम किया। लॉकडाउन में छूट दिये जाने के बाद ईंधन की मांग बढ़ने से कार्य क्षमता में सुधार आया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 महने में इन रिफाइनरियों की परिचालन क्षमता घटकर 30 से 40 प्रतिशत रह गई थी।

उस समय सड़कों पर वाहन नदारद थे। इसके बाद मई में इन रिफाइनरियों ने 1 करोड़ 63 लाख टन कच्चे तेल का शोधन किया। यह अप्रैल के मुकाबले 11 प्रतिशत अधिक था लेकिन एक साल पहले मई माह की तुलना में 24 प्रतिशत कम रहा। वहीं, दूसरी तरफ निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मई में लगातार तीसरे माह कच्चे तेल के प्रसंस्करण में कटौती की। कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी चलाती है। जामनगर परिसर स्थित उसकी दो रिफाइनरियों ने मई में 91.72 प्रतिशत की औसत क्षमता से परिचालन किया जबकि अप्रैल में यह औसत 94.8 प्रतिशत और मार्च 2020 में 95.4 प्रतिशत रहा था।

रिलायंस की रिफाइनरियों ने मई में 53.12 लाख टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया। यह एक साल पहले इसी माह के मुकाबले 12.5 प्रतिशत कम रहा। वहीं अप्रैल में इस रिफाइनरी परिसर में 53.14 लाख टन का प्रसंस्करण किया गया। इंडियन आयल कार्पोरेशन की देशभर में स्थित नौ रिफाइनरियों ने मई माह के दौरान औसतन 72.8 प्रतिशत की औसत क्षमता से परिचालन किया। वहीं अप्रैल में उन्होंने 53.2 प्रतिशत की क्षमता से परिचालन किया। इस दौरान देश में कच्चे तेल का उत्पादन मई माह के दौरान सात प्रतिशत घटकर 26 लाख टन रह गया हालांकि यह अप्रैल के 25.4 लाख टन से अधिक रहा। इस दौरान ओएनजीसी का उत्पादन 2.3 प्रतिशत घटकर 17.20 लाख टन रह गया। उद्योगों का उठाव घटने से इसमें कमी आई। लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधे बंद थे। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी मई माह में 16 प्रतिशत घटकर 2.3 अरब घन मीटर रह गया। उद्योगों के बंद रहने से गैस की मांग में कमी आई। इसलिये ओएनजीसी जैसी कंपनियों को उत्पादन घटना पड़ा।

भारत ने चीन, मलेशिया सहित चार देशों से एल्यूमीनियम फॉयल की डंपिंग जांच शुरू की

एजेंसी

नयी दिल्ली। भारत ने एल्यूमीनियम डंपिग के बारे में घरेलू विनिर्माताओं की शिकायत मिलने के बाद चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड से आने वाले एल्यूमीनियम फॉयल की कथित डंपिग के खिलाफ जांच शुरू की है। हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज, रविराज फॉयल्स और जिंदल इंडिया ने वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के समक्ष आवेदन कर इन देशों से आने वाले एल्यूमीनियम फॉयल के खिलाफ डंपिंग जांच का आग्रह किया। कंपनियों ने इन चार देशों से भारत में आयात किये जाने वाले '80 माइक्रोन और उससे कम दर्जे के एल्यूमीनियम फॉयल' के आयात की डंपिंग किये जाने की शिकायत की है। कंपनियों का आरोप है कि इन देशों से होने वाली डंपिंग के कारण घरेलू उद्योगों को नुकसान हो रहा है इसलिये इस आयात पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाया जाना चाहिये। डीजीटीआर ने एक अधिसूचना में कहा है कि आवेदकों द्वारा दिये गये सबूतों के आधार पर ''प्राधिकरण, इसके जरिये, जांच की शुरुआत करता है।''

जांच के दौरान यदि डीजीटीआर को यह पता चलता है कि संबंधित उत्पाद की डंपिंग की जा रही है और इससे घरेलू विनिर्माताओं पर प्रभाव पड़ रहा है तब ऐसी स्थिति में वह डंपिंग- रोधी शुल्क की सिफारिश करेगा। डीजीटीआर डंपिंग रोधी शुल्क की सिफारिश करता है और वित्त मंत्रालय इसे लगाता है।

चालू वित्त वर्ष में 5.3 प्रतिशत सिकुड़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था : इंडिया रेटिंग्स

एजेंसी

नयी दिल्ली। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 5.3 प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है। देश के इतिहास में यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की सबसे निचली वृद्धिदर होगी। रेटिंग एजेंसी ने बुधवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में संकुचन का यह छठा अवसर होगा। रेटिंग एजेंसी की रपट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पादन की रफ्तार और स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार श्रृंखला टूट गई है। विमानन, होटल और आतिथ्य क्षेत्र में गतिविधियां पूरी तरह ठप (हालांकि, अब कुछ गतिविधियां शुरू हो रही हैं) हो गई हैं। ऐसे में पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। रपट में कहा गया है कि पूरे वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी ही, प्रत्येक तिमाही के दौरान भी अर्थव्यवस्था नीचे आएगी। हालांकि, एजेंसी का मानना है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और पांच से छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगी। रपट कहती है कि आधार प्रभाव तथा घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति सामान्य होने की वजह से अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था वृद्धि दर्ज करेगी। इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5.3 प्रतिशत की गिरावट आएगी।

रपट कहती है कि यह देश के इतिहास में सबसे निचली जीडीपी की वृद्धि दर होगी। भारत के जीडीपी आंकड़े 1950-51 से उपलब्ध हैं। इसके अलावा यह छठा अवसर होगा जबकि अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। इससे पहले वित्त वर्ष 1957-58, 1965-66, 1966-67, 1972-73 और 1979-80 में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी। इससे पहले वित्त वर्ष 1979-80 में आर्थिक वृद्धि दर सबसे निचले स्तर पर गयी थी। तब देश की आर्थिक वृद्धि दर शेन्य से 5.2 प्रतिशत नीचे थी। सरकार ने कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए 12 मई, 2020 को 20.97 लाख करोड़ रुपये यानी जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। हालांकि, इंडिया रेटिंग्स की गणना के अनुसार इस पैकेज का सीधा वित्तीय प्रभाव सिर्फ 2.145 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 1.1 प्रतिशत है। इसमें मौद्रिक उपाय और आम बजट के मौजूदा प्रस्ताव शामिल नहीं हैं। रपट में कहा गया है कि आर्थिक पैकेज में ऋण और नकदी प्रबंधन के जो उपाय किए गए हैं और साथ में रिजर्व बैंक के पूर्व में घोषित उपायों से अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष के मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी। रपट कहती है कि कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन से पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग पक्ष की समस्या थी। रपट में कहा गया है कि लॉकडाउन और उसके अर्थव्यवस्था और आजीविका पर प्रभाव से उपभोक्ता मांग और प्रभावित हुई है।

ईरान से तेल आयात के मुद्दे पर भारत के प्रति ट्रंप ने नहीं दिखाई थी हमदर्दी : बोल्टन

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जॉन बोल्टन ने ईरान से तेल के आयात पर भारत के रुख का समर्थन करने को लेकर अमेरिकी विदेशी विभाग की आलोचना की है। साथ ही, उन्होंने यह दावा भी किया है कि उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मामले में हमदर्दी नहीं दिखाई थी। पूर्व एनएसए की बहुचर्चित पुस्तक ''द रूम वेयर इट हैपन्ड : ए व्हाइट हाउस मेमोयर'' मंगलवार को दुकानों पर आ गई। इस पुस्तक में कहीं-कहीं भारत का भी इस संदर्भ में जिक्र है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों को ईरान से तेल का आयात घटा कर शून्य पर लाने को कह रहे हैं। साथ ही, पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने का भी इसमें जिक्र आया है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने पिछले साल भारत और अन्य देशों से कहा था कि वे चार नवंबर (2019) तक ईरान से तेल का आयात करना पूरी तरह से समाप्त कर दें, अन्यथा उन्हें (ऐसा नहीं करने वाले देशों को) अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने और ईरान पर कठोर प्रतिबंध लगाने के एक साल बाद यह फैसला लिया गया। ईरान, भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। इस मामले में इराक और सऊदी अरब के बाद उसका स्थान आता है। ईरान ने अप्रैल 2017 और जनवरी 2018 के बीच 1.84 करोड़ टन कच्चे तेल की आपूर्ति की।

बोल्टन (71) ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ''विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ एक टेलीफोन वार्ता में, ट्रंप यह कहते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हमदर्दी प्रदर्शित करते नहीं दिखे कि, 'वह इस संकट से निकल जाएंगे। ' मुझे इसी तरह की एक और बातचीत का स्मरण हो रहा है, जिसमें छूट से जुड़े फैसलों को सहयोगी देशों को बताने में ट्रंप की रूचि नहीं दिख रही थी। '' उल्लेखनीय है कि अमेरिकी न्याय विभाग ने इस पुस्तक के लोकार्पण को रोकने के लिये अदालत का रुख किया था। ट्रंप प्रशासन ने यह आशंका जताई थी कि इससे गोपनीय जानकारी का खुलासा हो सकता है। हालांकि, एक संघीय न्यायाधीश ने बीते शनिवार को आदेश जारी किया कि बोल्टन अपनी पुस्तक का प्रकाशन कर सकते हैं। बोल्टन ने लिखा है, ''एक विदेशी नेता की वाशिंगटन यात्रा को देखते हुए ट्रंप ने एक सुझाव दिया था: 'उनके यहां आने से पहले यह कर लो और फिर कह देना कि मैं (ट्रंप) इस बारे में कुछ नहीं जानता,' तथा 'इसे सप्ताह के शुरू में ही कर लो। मैं इसके आसपास कहीं नहीं होना चाहता।'' इस विदेशी नेता ने भी छूट समाप्ति का विषय उठाया था। बोल्टन ने यह भी कहा कि वह (ट्रंप) नहीं चाहते थे कि विदेश विभाग के अधिकारी ईरान से तेल के आयात पर भारत का समर्थन या बचाव करें। उन्होंने लिखा है, ''सबसे खराब मामला भारत का था, जो अन्य देशों की तरह ही वैश्विक बाजार से कम कीमत पर ईरानी तेल खरीद रहा था क्योंकि ईरान तेल बेचने को लेकर बहुत व्यग्र था। भारत ने शिकायत भरे लहजे में कहा था कि यह सिर्फ इसलिए नुकसानदेह नहीं होगा कि उसे नये आपूर्तिकर्ताओं को ढूंढना होगा, बल्कि इसलिए भी कि नये स्रोत बाजार की मौजूदा कीमतों पर जोर देंगे।''

उन्होंने कहा, ''भारत के इस तर्क को समझा जा सकता है लेकिन यह समझ आने लायक नहीं है कि अमेरिकी अधिकारियों ने यह बात हमदर्दी के साथ दोहराई। बोल्टन ने पुलवामा हमले के बाद भारत-पाक संबंधों में तनाव का संभवतः जिक्र करते हुए लिखा है कि कई घंटों के फोन कॉल के बाद यह संकट खत्म हुआ। उन्होंने पुस्तक में लिखा है, ''कई घंटे के फोन कॉल के बाद संकट खत्म हुआ, शायद इसलिए कि सचमुच में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब दो परमाणु शक्तियां अपनी सैन्य क्षमताओं को हरकत में लाती हैं, तब इसे नजरअंदाज नहीं करने में ही भलाई है। उस वक्त किसी को परवाह नहीं थी, लेकिन मेरे लिए यह बात स्पष्ट थी : यह वही हुआ, जब लोग ईरान और उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिशों को गंभीरता से नहीं लेते हैं।'' पिछले साल 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हमले में सीआरपीएफ के 40 कर्मी शहीद हो गये थे। बोल्टन ने अफगानिस्तान पर अध्याय में इस बात का जिक्र किया है कि तालिबान के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप कश्मीर पर चर्चा करने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे। हालांकि, पूर्व एनएसए ने बातचीत के संदर्भ का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप ने कहा था, ''तब, कश्मीर पर जाएंगे, 'मैं सोमवार को मोदी से बात करना चाहता हूं।' व्यापार के कारण हमारे पास अपार शक्ति है।''

फिक्की ने कोविड-19 को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का सुझाव दिया

एजेंसी

नयी दिल्ली। उद्योग संगठन फिक्की ने सुझाव दिया है कि कोविड-19 को अधिसूचित बीमारी घोषित करना चाहिए और अब पूरा ध्यान संक्रमण को नियंत्रित कर इन मामलों में कमी लाने पर होना चाहिए। अधिसूचित बीमारी ऐसी बीमारी को कहते हैं, जिसके बारे में कानून के तहत सरकार को सूचना देना अनिवार्य है। फिक्की ने 'कोविड कंटेंनमेंट' नामक एक रिपोर्ट में कहा कि इस संक्रामक बीमारी के प्रकोप से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को फिर से आकार देना चाहिए।रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी का उचित तरीके से मुकाबला करने के लिए सभी स्तरों पर स्वास्थ्य कर्मियों को सक्षम बनाने की तत्काल आवश्यकता है। उद्योगमंडल ने स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के विकेंद्रीकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया है।

भारतीय कंपनी' की परिभाषा बदले सरकार : सीईएआई

एजेंसी

नयी दिल्ली। परामर्श देने वाले इंजीनियरों के शीर्ष संगठन 'कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (सीईएआई) ने सरकार से 'भारतीय कंपनी' की परिभाषा बदलने का आग्रह किया। संगठन की मांग है कि किसी भारतीय के 51 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली कंपनी को भारतीय कंपनी कहा जाना चाहिए।

मौजूदा वक्त में भारत में पंजीकृत और कर अदा करने वाली कंपनी को भारतीय कंपनी कहा जाता है। यह प्रावधान विदेशी कंपनियों को भारत में पंजीकरण कराने की अनुमति देता है।

वे यहां कर का भुगतान करती हैं लेकिन लाभ को वापस अपने स्वदेश ले जाती है। सीईएआई ने कहा कि कंपनी अधिनियम के तहत भारतीय कंपनी की परिभाषा बदले जाने की जरूरत है। इसके लिए न्यूनतम 51 प्रतिशत भारतीय व्यक्ति या इकाई की हिस्सेदारी वाली कंपनी को भारतीय कंपनी का दर्जा दिया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

सीईएआई के अध्यक्ष अमिताभ घोषाल ने कहा, '' आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सीईएआई का भारत सरकार से अनुरोध है कि वह कंपनी अधिनियम में तत्काल भारतीय कंपनी की परिभाषा में बदलाव करे।'' सीईएआई के पूर्व अध्यक्ष के. के. कपिला ने कहा कि मौजूदा प्रावधान विदेशी कंपनियों को यहां अनुषंगी के तौर पर कारोबार करने और भारतीय कंपनियों विशेषकर लघु उद्यमों (एमएसएमई) को मिलने वाले सभी लाभों का फायदा उठाने का मौका देता है। बयान के मुताबिक हाल में मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने 10 मोनोरेल के डिजाइन, विनिर्माण, आपूर्ति, परीक्षण की नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दिया था क्योंकि इसके लिए बोली लगाने वाली दोनों कंपनियां चीन की थी।

संभव है कि दोनों कंपनियां भारत में अपनी अनुषंगी स्थापित कर मौजूदा परिभाषा के हिसाब से 'भारतीय कंपनी' का लाभ लेते हुए दोबारा बोली प्रक्रिया में शामिल हो जाएं। कपिला ने इसलिए तत्काल इस परिभाषा में बदलाव की जरूरत बतायी।

सिर्फ खास किस्म के पीपीई के निर्यात पर ही प्रतिबंधः डीजीएफटी

एजेंसी

नयी दिल्ली। सरकार ने फैसला किया कि अब सिर्फ कुछ खास किस्म के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई), जैसे सभी श्रेणियों के चिकित्सा कवरऑल (ऊपर से नीचे तक पहनी जाने वाली एक पोशाक) और चश्मों के निर्यात पर ही प्रतिबंध होगा। इससे पहले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 31 जनवरी को कपड़ा और मास्क सहित सभी तरह के पीपीई के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। डीजीएफटी ने कहा कि उसने उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुए उसे सिर्फ उल्लेखित वस्तुओं तक सीमित कर दिया है और अन्य सभी वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है। जो पीपीई अभी भी प्रतिबंधित हैं, उनमें सभी श्रेणियों के कवरऑल, चिकित्सा चश्मे, गैर-चिकित्सा/ गैर-सर्जिकल मास्क को छोड़कर सभी तरह के मास्क, नाइट्राइल/एनबीआर दस्ताने और फेस शील्ड शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के कारण इन उत्पादों की अभी भी भारी मांग है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने इस फैसले की तारीफ की और इस अधिसूचना के कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने की इच्छा जताई।

रेलवे ने वेंडरों के लिए नियमों को आसान बनाया

नयी दिल्ली। रेलवे ने खरीदारी के नियमों को आसान बनाते हुए फैसला किया है कि किसी भी वेंडर अनुमोदन एजेंसी द्वारा किसी मद के लिए अनुमोदित वेंडर को देश की सभी रेल इकाइयों द्वारा उस खास मद के लिए अनुमोदित वेंडर माना जाएगा। इस फैसले से वेंडरों का समय बचेगा और उन्हें विभिन्न अनुमोदन एजेंसियों से संपर्क करने की जरूरत नहीं होगी। रेल मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इस फैसले से किफायत को बढ़ावा मिलेगा और सार्वजनिक खरीद में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। अभी तक एक एजेंसी से अनुमोदित वेंडर को दूसरे प्रतिष्ठान में खरीद के लिए स्वाभाविक रूप से पात्र नहीं समझा जाता था और वेंडरों को विभिन्न प्रतिष्ठानों के समक्ष अनुमोदन के लिए आवेदन करना पड़ता था। इस फैसले से रेलवे की खरीद में पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सौर उपकरण पर अगस्त से सीमा शुल्क लगाने का प्रस्तावः आर के सिंह

एजेंसी

नयी दिल्ली। बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सौर सेल, मोड्यूल्स और इनवर्टर पर अगस्त से मूल सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है।

सिंह ने उद्योग संगठनों के साथ वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये हुई बैठक में प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। यह बैठक आत्मनिर्भर अभियान और 'मेक इन इंडिया' पहल की सफलता सुनिश्चित के उपायों पर चर्चा के लिये बुलायी गयी थी। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''केंद्रीय मंत्री ने बैठक में मंत्रालय के अगस्त 2020 से सौर मोड्यूल, सौर सेल और सौर इनवर्टर पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाने के प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी।'' बयान में मंत्री के हवाले से कहा गया है कि सीमा शुल्क की दरों के बारे में स्थिति बिल्कुल साफ की जाएगी ताकि सरकार की नीतियों को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं हो। सिंह ने यह भी कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुछ आयात वस्तुओं के लिये रियायती सीमा शुल्क प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। इसकी तिथि के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी।

फिलहाल सौर उपकर पर कोई बीसीडी नहीं है। हालांकि सौर सेल पर रक्षोपाय शुल्क 15 प्रतिशत है। यह 30 जुलाई 2020 से शून्य हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत ने जुलाई 2018 में चीन और मलेशिया से आयातित सौर सेल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क दो साल के लिये लगाया था। इसका मकसद आयात में तीव्र वृद्धि से घरेलू विनिर्माताओं के हितों की रक्षा करना था।

सरकार ने 30 जुलाई 2018 से 29 जुलाई 2019 तक 25 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क लगाया था। यह धीरे-धीरे कम होकर 30 जुलाई 2019 से 29 जनवरी 2020 तक 20 प्रतिशत और 30 जनवरी, 2020 से 29 जुलाई 2020 तक 15 प्रतिशत पर आ गया। मंत्री ने यह भी कहा कि अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में मॉडल और विनिर्माताओं की मंजूरी वाली सूची एक अक्टूबर से प्रभाव में आएगी जैसा कि पहले घोषित किया गया था।

चीन से आयात पर निर्भरता कम करेगा वाहन कलपुर्जा उद्योग

आईपीटी नेटवर्क

नयी दिल्ली। देश का वाहन कलपुर्जा उद्योग सीमा तनाव के बीच चीन से आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रहा है। करीब 57 अरब डॉलर का वाहन कलपुर्जा उद्योग 'स्थानीयकरण' तथा चीन के आयात से जोखिम को कम करने की पहल कर रहा है। भारतीय वाहन कलपुर्जा विनिर्माता संघ (एसीएमए) ने बुधवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही घरेलू वाहन उद्योग भी चीनी आयात पर निर्भरता कम करना चाहता है।

कोरोना वायरस महामारी की वजह से वाहन उद्योग को महत्वपूर्ण कलपुर्जों की कमी से जूझना पड़ा

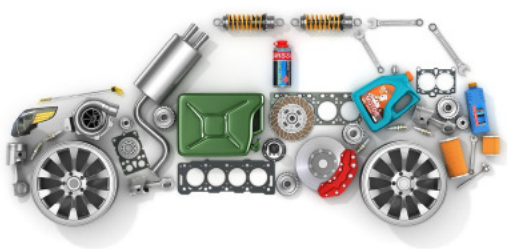

था। अभी चीन से बाहर की कंपनियां वाहन कलपुर्जों की प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में भारत ने 17.6 अरब डॉलर के वाहन कलपुर्जों का आयात किया था। इसमें से 27 प्रतिशत यानी 4.75 अरब डॉलर का आयात चीन से हुआ था। एसीएमए के महानिदेशक विनी मेहता ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''कोविड-19 महामारी और उसके चलते हुए लॉकडाउन की वजह से सभी अर्थव्यवस्थाओं और उद्योगों ने आयात पर निर्भरता घटाने पर विचार करना शुरू कर दिया है।''

उन्होंने कहा कि देश के वाहन उद्योग ने अपने जोखिम को कम करना शुरू किया है। वह गंभीरता से स्थानीयकरण पर ध्यान दे रहा है। मेहता ने कहा कि भारत-चीन के बीच हालिया विवाद के बाद यह प्रक्रिया और तेज होगी। उन्होंने कहा कि इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि उद्योग को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। कंपनियों और सरकार को साथ मिलकर इसकी रूपरेखा बनानी होगी और उसी के अनुरूप काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि न तो सरकार अकेले ऐसा कर सकती है और न ही उद्योग। दोनों को साथ काम करना होगा। मेहता ने कहा कि घरेलू वाहन कलपुर्जा उद्योग की वृद्धि के लिए सरकार को कारोबार सुगमता, सस्ती दर पर पूंजी की उपलब्धता, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा की लागत पर ध्यान देना होगा।

दूसरे देशों के लिये के दरवाजे बंद करने का फायदा नहीं, हां सीमा पर गड़बड़ी करने वाले अपवादः सीईए

एजेंसी

कोलकाता। भारत-चीन के बीच बढ़ते तनाव तथा वहां से आने वाले सामान पर पाबंदी लगाने की चर्चा के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमणियम ने कहा कि अन्य देशों के लिये दरवाजे बंद करने से भारत को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने आयात पर रोक लगाने और घरेलू उत्पादन पर जोर की नीति का अनुसरण 1991 तक किया और उसके बाद इस रुख को महत्व नहीं दिया गया। एमसीसीआई द्वारा आयोजित एक वेबिनार (इंटरनेट के जरिये होने वाला सेमिनार) को संबोधित करते हुए सुब्रमणियम ने कहा, ''भारत को अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना है और अन्य से खुद को अलग करने से मदद नहीं मिलने वाली।'' हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ''उपरोक्त बाद कहने के बावजू इसके कुछ अपवाद भी हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि जो देश सीमा पर समस्या पैदा कर रहे हैं, उनके साथ कारोबार जारी रहना चाहिए।'' मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह बात ऐसे समय कही है कि जब भारत-चीन सीमा पर हिंसक झड़प के बाद विभिन्न तबकों से चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग तेज हो रही है। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गये। सुब्रमणियम के अनुसार अभी यह साफ नहीं है कि अर्थव्यवस्था में मांग कब से जोर पकड़ेगी। उन्होंने कहा, ''मौजूदा अनिश्चिता शुद्ध रूप से स्वास्थ्य कारणों से है और यह संभवतः तभी दूर होगी जब कोविड-19 के इलाज के लिये टीका उपलब्ध होगा।''

बैंकों ने 19 लाख एमएसएमई, अन्य कंपनियों के लिये 79 हजार करोड़ के कर्ज को मंजूरी दी

एजेंसी

नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैंकों ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिये 3 लाख करोड़ रुपये के आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 20 जून तक 19 लाख एमएसएमई और अन्य कंपनियों के लिये 79,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसमें से 35,000 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) के लिये घोषित 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना है। इसके तहत कंपनियां अपने मौजूदा कर्ज का 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त कर्ज निर्धारित ब्याज पर ले सकती हैं।

मंत्रालय ने बयान में कहा, सरकर ने एमएसएमई के लिये जो कदम उठाया है, वह अब जोर पकड़ रहा है। सरकार की गारंटी वाली आपात ऋण सुविधा के तहत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों ने 20 जून 2020 तक 79,000 करोड़ रुपये कर्ज मंजूर किये हैं। इसमें से 35,000 करोड़ रुपये पहले वितरित किये जा चुके हैं। योजना के तहत कर्ज देने वाले प्रमुख बैंक में एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और केनरा बैंक शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार इससे 19 लाख एमएसएमई और अन्य कंपनियों को 'लॉकडाउन' के बाद अपना कामकाज शुरू करने में मदद मिली है। इसके अलावा आरबीआई की मार्च-अप्रैल 2020 में घोषित विशेष नकदी सुविधा के तहत सिडबी (भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), छोटी राशि के कर्ज देने वाले संस्थानों और एमएसएमई तथा छोटे कर्जदारों को ऋण देने के लिये बैंकों को 10,200 करोड़ रुपये वितरित किये है। वहीं राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनियों के लिये 10,000 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। सिडबी और एनएचबी द्वारा पुनर्वित्त मौजूदा योजनाओं के अलावा है जिसके तहत 30,000 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं।

सेबी की आय 2018-19 में 13 प्रतिशत बढ़कर 963 करोड़ रही

आईपीटी नेटवर्क

नयी दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी की कुल आय 2018- 19 में 13 प्रतिशत बढ़कर 963 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। फीस और ग्राहक अंशदान से होने वाली आय बढ़ने से सेबी की आय बढ़ी है। सेबी के सालाना लेखा- जोखा के मुताबिक वर्ष के दौरान उसका कुल खर्च भी बढ़कर 492.34 करोड़ रुपये तक पहुंच गया जो कि एक साल पहले 414.46 करोड़ रुपये रहा था। इस दौरान अन्य प्रशासनिक खर्च 121 करोड़ रुपये से बढ़कर 131 करोड़ रुपये और प्रतिष्ठान खर्च 244 करोड़ रुपये से बढ़कर 293 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान पूंजी बाजार नियामक की फीस से होने वाली आय 624 करोड़ रुपये से बढ़कर 750 करोड रुपये और अन्य आय 10 करोड़ रुपये से बढ़कर 17 करोड़ रुपये हो गई। वहीं निवेश से नियामक की आय 207 करोड़ रुपये से घटकर 180 करोड़ रुपये रह गई।

कुल मिलाकर वर्ष 2018-19 के दौरान पूंजी बाजार नियामक की कुल आय एक साल पहले के 854.78 करोड़ रुपये से बढ़कर 963.59 करोड़ रुपये हो गई। यह वृद्धि 13 प्रतिशत रही। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का गठन 1988 में हुआ था। शेयर बाजार में हर्षद मेहता घोटाला सामने आने के बाद 1992 में सेबी कानून पारित हुआ और सेबी को सांविधिक शक्तियां प्राप्त हुईं। सेबी को शेयर ब्रोकरों से मिलने वाली फीस, शेयर बाजारों से मिलने वाली सूचीबद्धता फीस, ग्राहकों से अंशदन और नवीनीकरण तथा आवेदन आदि से होने वाली आय उसकी कुल कमाई में शामिल होती है।

सेबी का काम प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। इसके साथ ही बाजार का नियमन और उसका संवर्धन भी उसके अधिकार क्षेत्र में है। इसके साथ ही अनुचित व्यापार व्यवहार गतिविधियों, भेदिया कारोबार और अन्य साठगांठ वाली गतिविधियों पर भी वह नजर रखता है।

लार्सन एण्ड टुब्रो ने रिफाइनरी, पेट्रो- रसायन परियोजना के लिये केबीआर के साथ समझौता किया

नयी दिल्ली। इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एण्ड टुब्रो (एल एण्ड टी) ने कहा कि उसने रिफाइनरी और पेट्रोरसायन परियोजनाओं में माड्यूलर प्रोसेस प्लांट लगाने के लिये केबीआर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। केबीआर के साथ आपसी सहमति के ज्ञापन (एमओयू) पर एल एण्ड टी की इकाई एल एण्ड टी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग ने हस्ताक्षर किये हैं। इंजीनियरिंग कंपनी ने अपने वक्तव्य में कहा है, ''लार्सन एण्ड टुब्रो की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी एल एण्ड टी हाइड्रकार्बन इंजीनियरिंग (एलटीएचई) ने रिफाइनरी और पेटोरसायन परियोजनाओं के लिये माड्यूलर प्रोसेस प्लांट बनाने के वास्ते केबीआर के साथ आपसी सहमति के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।'' समझौते की शर्तों में कहा गया है कि केबीआर और एलटीएचई आपस में कारोबारी संभावनाओं को तलाशने के लिये आपस में गठबंधन करेंगे। इसके तहत एलटीएचई वैश्विक परियोजनाओं में केबीआर की कुछ खास प्रौद्योगिकी के लिये बोली लगायेगी। इनमें भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका क्षेत्र में खास जोर रहेगा।

एलटीएचई के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुब्रमणियम शर्मा ने कहा कि रिफाइनरी और पेट्रोरसायन क्षेत्र में एल एण्ड टी का 25 साल का बेहतरीन ट्रैक रिकार्ड है। केबीआर के साथ इस एमओयू के जरिये एलटीएचई अपनी बेहतर इंजीनियरिंग, विश्वस्तरीय माड्यूलर फेब्रीकेशन सुविधा और परियाजना प्रबंधन एवं निर्माण क्षेत्र की मूल ताकत के साथ ही अपने ग्राहकों को सुरक्षित, विश्वसनीय और बेहतर निदान उपलबध करा सकेगी।''

एसबीआई ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत 13,212 किलो सोना जुटाया

आईपीटी नेटवर्क

नयी दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक उसने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) के तहत 13,212 किलोग्राम घरेलू और संस्थागत सोना जुटाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक ने 2019-20 में जीएमएस के तहत 3,973 किलोग्राम सोना जुटाया था। सरकार ने आम लोगों और ट्रस्टों के पास रखे सोने का इस्तेमाल करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। एसबीआई ने रिपोर्ट में कहा, ''वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने 3,973 किलोग्राम सोना जुटाया, जिसके साथ अब तक कुल 13,212 किलोग्राम सोना जुटाया जा चुका है।''

सरकार ने घरों में और संस्थानों के पास बिना उपयोग वाले सोने को जुटाने के लिए नवंबर 2015 में जीएमएस की शुरुआत की थी। योजना का मकसद बेकार पड़े सोने का इस्तेमाल कर सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना था। बैंक ने आगे कहा कि 2019-20 के दौरान उसने 647 किलोग्राम (243.91 करोड़ रुपये) सोना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) के माध्यम से जुटाया।

भारतीय कंपनियों की रेटिंग और नीचे आने का जोखिम : एसएंडपी ग्लोबल

एजेंसी

नयी दिल्ली। रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि भारत में कंपनियों की रेटिंग या साख के और नीचे जाने का जोखिम है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि यदि कंपनियों की आय में सुधार 18 महीने से अधिक लंबा खिंचता है जो उनकी साख और घट सकती है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंगस ने बयान में कहा कि भारतीय कंपनियों की करीब 35 प्रतिशत क्रेडिट रेटिंग्स का परिदृश्य या तो नकारात्मक है या वह नकारात्मक प्रभाव के साथ 'निगरानी' में है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के साख विश्लेषक नील गोपालकृष्णन ने कहा, ''ज्यादातर रेटिंग्स के मामले में हमारा मानना है कि कंपनियों की आय अगले 12 से 18 माह में सुधर जाएगी। यदि यह सुस्ती इससे अधिक लंबी खिंचती है, तो कंपनियों की रेटिंग के और नीचे जाने का जोखिम रहेगा।''गोपालकृष्णन ने कहा कि नकारात्मक परिदृश्य और निगरानी वाली सात में से दो कंपनियों की रेटिंग्स अव्यवहार्य ग्रेड श्रेणी में है। इन कंपनियों की आमदनी को लेकर अधिक उतार-चढ़ाव रहने की आशंका है।

ऐसे में इनकी रेटिंग के नीचे जाने का जोखिम और अधिक बढ़ जाता है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारतीय कंपनियां साख में कमी को लेकर बेहतर स्थिति में नहीं हैं। इसकी वजह है कि कि इन कंपनियों का पूंजीगत व्यय ऋण वित्तपोषित है। इसके अलावा इन कंपनियों द्वारा पिछले दो-तीन साल में अधिग्रहण किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से कंपनियों की रेटिंग पहले ही नीचे आ रही है। उदाहरण के लिए एकल बी रेटिंग वाली कंपनियों की संख्या 2019 के अंत तक बढ़कर 33 प्रतिशत हो गई, जो 2016 में 13 प्रतिशत थी।

बैंक ऑफ बड़ौदा को चौथी तिमाही में 507 करोड़ रुपये का मुनाफा

एजेंसी

मुंबई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बडौदा ने कहा है कि मार्च 2020 तिमाही के दौरान उसने 507 करोड़ रुपये का कर पश्चात मुनाफा हासिल किया। इस दौरान एनपीए (अवरुद्ध ऋणोंत) के लिए कम प्रावधान से बैंक को परिणाम बेहतर दिखाने में मदद मिली। उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल 2019 से बैंक में देना बैंक और विजया बैंक का विलय प्रभावी हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इससे पिछले साल की समान अवधि में 8,875 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि दर्ज की थी। बैंक ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले मार्च 2020 तिमाही में गैर-निष्पादित ऋणों के लिए प्रावधान 69.23 प्रतिशत घटकर 10,368 करोड़ रुपये से 3,190 करोड़ रुपये रह गया। बीते वित्त वर्ष की पूरी अवधि के दौरान बैंक ने 546 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हासिल किया, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक को 8,340 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ था।

1 जुलाई से चातुर्मास, श्राद्ध पक्ष के बाद 20 से 25 दिन देरी से आएंगे सारे त्योहार, 160 साल बाद लीप ईयर और आश्विन अधिकमास एक ही साल में

1 जुलाई को देवशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू हो रहे हैं। चातुर्मास मतलब वो चार महीने जब शुभ काम वर्जित होते हैं, त्योहारों का सीजन होता है। देवशयनी एकादशी से देवप्रबोधिनी एकादशी के बीच के समय को चातुर्मास कहते हैं। इस बार अधिक मास के कारण चातुर्मास चार की बजाय पांच महीने का होगा। श्राद्ध पक्ष के बाद आने वाले सारे त्योहार लगभग 20 से 25 दिन देरी से आएंगे। इस बार आश्विन माह का अधिकमास है, मतलब दो आश्विन मास होंगे। इस महीने में श्राद्ध और नवरात्रि, दशहरा जैसे त्योहार होते हैं। आमतौर पर श्राद्ध खत्म होते ही अगले दिन से नवरात्रि आरंभ हो जाती है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध खत्म होंगे और अगले दिन से अधिकमास शुरू हो जाएगा, जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। 17 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ होगी। इस तरह श्राद्ध और नवरात्रि के बीच इस साल एक महीने का समय रहेगा। दशहरा 26 अक्टूबर को और दीपावली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी रहेगी और इस दिन चातुर्मास खत्म हो जाएंगे।

160 साल बाद लीप ईयर और अधिक मास एक ही साल में

उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा के अनुसार, 19 साल पहले 2001 में आश्विन माह का अधिकमास आया था। अंग्रेजी कैलेंडर का लीप ईयर और आश्विन के अधिकमास का योग 160 साल बाद बन रहा है। इससे पहले 1860 में ऐसा अधिकमास आया था, जब उसी साल लीप ईयर भी था।

हर तीन साल में आता है अधिकमास

पं. शर्मा के अनुसार एक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, जबकि एक चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। ये अंतर हर तीन वर्ष में लगभग एक माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए हर तीन साल में एक चंद्र मास अतिरिक्त आता है, जिसे अतिरिक्त होने की वजह से अधिकमास का नाम दिया गया है। अधिकमास के पीछे पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगर अधिकमास नहीं होता तो हमारे त्योहारों की व्यवस्था बिगड़ जाती है। अधिकमास की वजह से ही सभी त्योहारों अपने सही समय पर मनाए जाते हैं।

चातुर्मास में तप और ध्यान करने का विशेष महत्व

चार्तुमास में संत एक ही स्थान पर रुककर तप और ध्यान करते हैं। चातुर्मास में यात्रा करने से यह बचते हैं, क्योंकि ये वर्षा ऋतु का समय रहता है, इस दौरान नदी-नाले उफान पर होते है तथा कई छोटे-छोटे कीट उत्पन्न होते हैं। इस समय में विहार करने से इन छोटे-छोटे कीटों को नुकसान होने की संभावना रहती है। इसी वजह से जैन धर्म में चातुर्मास में संत एक जगह रुककर तप करते हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। देवउठनी एकादशी के बाद विष्णुजी फिर से सृष्टि का भार संभाल लेते हैं।

अधिकमास को मलमास क्यों कहते हैं?

अधिकमास में सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। इस पूरे माह में सूर्य संक्राति नहीं रहती है। इस वजह से ये माह मलिन हो जाता है। इसलिए इसे मलमास कहते हैं। मलमास में नामकरण, यज्ञोपवित, विवाह, गृहप्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी जैसे शुभ कर्म नहीं किए जाते हैं।

रावण और मारीच का प्रसंग

जब भी कोई बुरा व्यक्ति हमारे सामने झुकता है तो हमें और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, वरना हम मुसीबत में फंस सकते हैं

गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीरामचरित मानस में रावण और मारीच के एक प्रसंग बताया गया है। इस प्रसंग में रावण सीता का हरण करने की इच्छा से मारीच के पास पहुंचता है। वह मारीच की मदद से सीता का हरण करना चाहता था। इस प्रसंग में बताया गया है कि जब कोई बुरा व्यक्ति हमारे सामने झुकता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए।

रावण सीता का हरण करने के लिए लंका से निकलकर अपने मामा मारीच के पास पहुंचता है और प्रणाम करता है। मारीच रावण को झुका देखकर समझ जाता है कि अब भविष्य में कोई संकट आने वाला है।

इस संबंध श्रीरामचरित मानस में लिखा है कि-

नवनि नीच कै अति दुखदाई। जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई।।

भयदायक खल कै प्रिय बानी। जिमि अकाल के कुसुम भवानी।।

इस चौपाइयों का सरल अर्थ यह है कि रावण को इस प्रकार झुका देखकर मारीच सोचता है कि किसी नीच व्यक्ति का नमन करना भी दुखदाई है। मारीच रावण का मामा था, लेकिन रावण राक्षसराज और अभिमानी था। वह बिना कारण किसी के सामने झुक नहीं सकता था। मारीच ये बात जानता था और उसका झुकना किसी भयंकर परेशानी का संकेत था। तब भयभीत होकर मारीच ने रावण को प्रणाम किया।

मारीच सोचता है कि जिस तरह कोई धनुष झुकता है तो वह किसी के लिए मृत्यु रूपी बाण छोड़ता है। जैसे कोई सांप झुकता है तो वह डंसने के लिए झुकता है। जैसे कोई बिल्ली झुकती है तो वह अपने शिकार पर झपटने के लिए झुकती है। ठीक इसी प्रकार रावण भी मारीच के सामने झुका था। किसी नीच व्यक्ति की मीठी वाणी भी बहुत दुखदायी होती है, यह ठीक वैसा ही है जैसे बिना मौसम का कोई फल। मारीच अब समझ चुका था कि भविष्य में उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है।

रावण मारीच को स्वर्ण मृग बनकर सीता को लुभाने के लिए कहता है। मारीच रावण की बात टाल नहीं सकता था। इसीलिए वह स्वर्ण मृग बनकर सीता के सामने पहुंच गया। सीता ने सोने के हिरण को देखकर श्रीराम से उसे लेकर आने के लिए कहा। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रीराम हिरण के पीछे चले गए। श्रीराम के बाण से मारीच मारा गया। कुछ देर बाद लक्ष्मण भी श्रीराम की खोज में चले गए और रावण ने सीता का हरण कर लिया।

इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें बुरे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जब ऐसे लोग हमारे सामने झुकते हैं तो और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है। वरना हम मुसीबतों में फंस सकते हैं।

कोरोना संक्रमण के दौरान अपनाएं योग

योग को प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। हाल ही में बिहेवियरल मैडिसिन पत्रिका में छपे एक शोध के अनुसार योग आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और शरीर में जलन को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। योग के निरंतर अभ्यास से तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स में प्रभावशाली रूप से कमी आती है, तंत्रिका तंत्र मजबूत बनता है और यह लसिका प्रणाली (लिमफैटिक सिस्टम)को क्रियाशील करता है। साथ ही साथ यह शरीर से विषैले तत्वों को भी बाहर निकालता है। प्रतिदिन किए जाने वाले कुछ योगाभ्यास चिंता कम और मन को शांत करते हैं जिसके चलते नींद की गुणवत्ता में सुधार आता है। एक अच्छी नींद रोग निवारक है और एक स्वस्थ प्रतिरोधक तंत्र को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान देती है।

इन आसनों से बचेंगे कोरोना से

यहां कुछ योगाभ्यास दिए गए हैं जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। 'श्री श्री योग प्रोटोकॉल' में आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल हैं। इस प्रोटोकॉल में दिए गए आसनों को इन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे उलटना-पलटना,अंगों को मोड़ना और छाती को फैलाना। उलटने-पलटने वाला कोई भी आसन रक्त प्रवाह में सुधार करता है और लसिका प्रणाली की कार्यकारिणी को बेहतर बनाता है जिसमें शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं जिसके चलते प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है।

लसिका तंत्र का सबसे पहला कार्य लसिका को पूरे शरीर में प्रवाहित करना है। यह एक प्रकार का द्रव्य होता है जिसमें संक्रमण से लड़ने वाली सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। उलटने-पलटने वाले आसन विशेष रूप से हमारी नाड़ियों और फेफड़ों में कफ के जमाव को हटाते हैं और उनमें संक्रमण की सम्भावना को कम कर देते हैं। मस्तिष्क में हुए रक्त प्रवाह में सुधार के कारण मन में विश्राम और शांति की भावना स्वत: उत्पन्न हो जाती है जो इन अभ्यासों को करने से होता है। हालांकि उच्च रक्तचाप वाले लोगों को उलटने-पलटने वाले आसन करने से बचना चाहिए और उन्हें इनका अभ्यास एक विशेषज्ञ की देखरेख में करना चाहिए।

आसन जैसे - हस्त पदासन या अर्द्ध उत्थान आसन (खड़े होकर आगे की ओर झुकना), अधोमुख श्वान आसन (नीचे झुके हुए कुत्ते की मुद्रा), सर्वांगासन (कंधों पर खड़े होना) या विपरीत करणी (टांगों को उठाना) पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को सुधारने में मदद करेंगे।

पाचन तंत्र की भूमिका

पाचन तंत्र की हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। आयुर्वेद के अनुसार खराब पाचन और पाचन नली का ठीक प्रकार से ध्यान न रखने से आंव और कफ बनता है जो अंतत: मन को प्रभावित करता है और फेफड़ों में भी कफ को जमा देता है। कुछ अभ्यासों में पेट को दबाने वाले और शरीर को मोड़ने वाले आसनों को शामिल करने से हम अपने पेट, आंतों, गुर्दों और अन्य आंतरिक अंगों में रक्त के संचार को बढ़ा सकते हैं ताकि पाचन बेहतर तरीके से हो और वहां मौजूद विषैले तत्व बाहर निकल जाएं। वक्रासन या अर्द्ध मत्स्येंद्र आसन (बैठकर रीढ़ की हड्डी को घुमाना),नटराज आसन (लेटकर रीढ़ की हड्डी को घुमाना), शिशु आसन, पवन मुक्तासन और पश्चिमोत्तासन (बैठकर आगे झुकना) आपको स्वास्थ्यलाभ प्रदान करेंगे।

जो आसन छाती फैलाने में मदद करते हैं वे थोरेसिक कैविटी और फेफड़ों में रक्त के संचार को बढ़ाने में मदद करते हैं, वे बहुत लाभकारी हैं। आसन जैसे मत्स्यासन, भुजंगासन, धनुरासन, अर्द्ध चक्रासन (खड़े होकर पीछे की ओर मुड़ना) छाती को फैलाने वाले आसन हैं और इन्हें अपने दैनिक योगाभ्यास में शामिल किया जा सकता है।

नोट : निरंतर योगाभ्यास से बेहतर स्वास्थ्य लाभ होता है लेकिन जान लीजिए कि यह चिकित्सीय उपचार का विकल्प नहीं है। आपका कोई इलाज चल रहा है तो डॉक्टर की सलाह और प्रशिक्षित योग शिक्षक की देखरेख में अभ्यास करें।

ऑडी ने 'आरएस-7 स्पोर्टबैक' कार की बुकिंग शुरू की, - अगस्त से करेगी डिलिवरी

आईपीटी नेटवर्क

इंदौर। लक्जरी कार बनाने वाली जर्मनी की कंपनी ऑडी ने अपनी नयी 'आरएस-7 स्पोर्टबैक' कार की बुकिंग शुरू कर दी। इसे अगले महीने भारतीय बाजार में पेश किए जाने की संभावना है। कंपनी अगस्त से इसकी डिलिवरी शुरू करेगी। हालांकि कंपनी ने इस कार की कीमत का खुलासा नहीं किया है। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पांच लोगों के बैठने की क्षमता वाली यह कार 'आरएस-7 स्पोर्टबैक' की दूसरी पीढ़ी की कार है। इसकी पहली पीढ़ी की कार को भारतीय बाजार में 2015 में उतारा गया था। विज्ञप्ति के मुताबिक ग्राहक 10 लाख रुपये का आरंभिक भुगतान कर ऑनलाइन या डीलरशिप पर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी के भारतीय परिचालन के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, '' हमने भारत में 'आरएस-7 स्पोर्टबैक' की बुकिंग शुरू कर दी है। इस दूसरी पीढ़ी के कार को उन सभी खूबियों के साथ उतारा गया है जिसकी वजह से इसकी पहली पीढ़ी की कार ने भारतीय बाजार में अपनी धमक बनायी थी। इसकी चौड़ी डिजाइन इसे अलग पहचान देती है।'' उन्होंने कहा कि ग्राहक कंपनी के पूर्णतया सैनेटाइज डीलरशिप पर तो जा ही सकते हैं। वहीं ऑनलाइन स्टोर पर इस कार से जुड़ी सभी जानकारियां भी उपलब्ध करायी गयी हैं। ऑनलाइन मंच पर कार का 360 डिग्री मॉडल भी मौजूद है जो कार के बाहरी लुक के साथ-साथ अंदरूनी लुक को भी दिखाता है। बाजार में इस कार के मर्सडीज-एएमजी ई-63 एस और बीएमडब्ल्यू एम5 को चुनौती देने की उम्मीद है।

रियल एस्टेट निवेश के लिए सबसे पसंदीदा परिसंपत्ति, लेकिन खरीदार हैं सतर्क

आईपीटी नेटवर्क

नयी दिल्ली। हाउसिंग डॉट कॉम और नारेडको के एक सर्वेक्षण के मुताबिक रियल एस्टेट निवेश के लिए सबसे पसंदीदा परिसंपत्ति के रूप में उभरा है, लेकिन संभावित घर खरीदारों, जो अभी किराये के मकान में रह रहे हैं, का मानना है कि कीमतें अभी भी बहुत अधिक हैं और इन कीमतों पर वे घर नहीं खरीद सकते हैं। हाउसिंग डॉट कॉम ने कहा कि यह सर्वेक्षण अप्रैल-मई में आठ शहरों में किया गया और इसके तहत 3,000 संभावित घर खरीदारों की राय ली गई। हाउसिंग डॉट कॉम एलारा टेक्नालॉजीज का हिस्सा है, जिसके पास प्रॉपटाइगर और मकान डॉ कॉम का स्वामित्व भी है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार रियल एस्टेट निवेश के लिए सबसे पसंदीदा परिसंपत्ति (35 प्रतिशत) है और उसके बाद सोना (28 प्रतिशत), सावधि जमा (22 प्रतिशत) और शेयर बाजार (16 प्रतिशत) का स्थान है। सर्वेक्षण में शामिल होने वाले 59 प्रतिशत को लगता है कि आर्थिक हालात मौजूदा स्तरों पर रहेंगे या आने वाले छह महीनों में इसमें कुछ सुधार हो सकता है। करीब 53 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने आने वाले छह महीनों के लिए घर की अपनी खोज को स्थगित कर दिया है। वेब-प्रेस सम्मेलन में यह रपट जारी करते हुए हाउसिंग डॉट कॉम, मकान डॉटकॉम ' प्रॉप टाइगर डॉटकॉम के ग्रुप सीईओ, ध्रुव अग्रवाला ने कहा, 'हमारे सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि फ्लैट्स की खोज करने वाले संभावित होमबॉयर्स ने लिक्विडिटी की चिंताओं और कोविड महामारी से बनी अनिश्चितता के कारण अभी अपने घर की खोज पर विराम लगाया है। लेकिन, उनमें से अधिकांश धीरे-धीरे आने वाले महीनों में बाजार में वापस आने लगेंगे। ' उन्होंने कहा इस सर्वेक्षण ने फिर से स्थापित किया है कि विश्वसनीय डेवलपर्स और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी को संभावित ग्राहकों द्वारा पसंद किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर वास्तविक उपयोगकर्ता हैं।

कमजोर मांग से ग्वारसीड वायदा कीमतों में गिरावट

एजेंसी

नयी दिल्ली। वायदा कारोबार में बुधवार को ग्वारसीड की कीमत 12 रुपये की गिरावट के साथ 3,668 रुपये प्रति 10 क्विन्टल रह गयी। एनसीडीईएक्स में ग्वारसीड के जुलाई महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 12 रुपये अथवा 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,668 रुपये प्रति 10 क्विन्टल रह गयी जिसमें 26,705 लॉट के लिए कारोबार हुआ। इसी प्रकार, ग्वारसीड के अगस्त महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 11 रुपये अथवा 0.3 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,659 रुपये प्रति 10 क्विन्टल रह गयी जिसमें 15,675 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार सूत्रों के अनुसार, उत्पादक क्षेत्रों से आपूर्ति बढ़ने के कारण यहां वायदा कारोबार में ग्वारसीड कीमतों में गिरावट आई।

चेन्नई में रुका चीनी सामानों का कस्टम क्लीयरेंस

एजेंसी

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की नापाक हरकतों के कारण भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। इसका असर दोनों देशों के बीच कारोबार पर भी पड़ रहा है। भारत ने चेन्नई में चीनी सामानों के लिए कस्टम क्लीयरेंस रोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक अब इस सामान की पूरी तरह जांच करने के बाद ही इसे क्लीयरेंस मिलेगी।

हालांकि चीनी सामान का क्लीयरेंस रोकने के लिए कोई औपचारिक निर्देश नहीं दिए गए हैं लेकिन चीन से आई खेप को 100 फीसदी चेकिंग से गुजरना पड़ सकता है।

सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात से क्लीयरेंस रोक दी गई है। सरकार के अंदर यह सोच है कि कुछ समय के लिए चीनी सामान का क्लीयरेंस पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों तक ही सीमित रखा जाए।

चीनी कंपनियों के लिए अहम है चेन्नई बंदरगाह

देश में टेलीकॉम पार्ट्स और इक्विपमेंट के आयात के लिए चेन्नई बंदरगाह अहम है। भारत में कारोबार कर रहीं चीन की कई कंपनियां चेन्नई बंदरगाह के जरिये ही अपना सामान मंगाती हैं। अब चीन से आने वाले सामान की शत-प्रतिशत जांच होगी। अब तक इसकी रेंडम जांच होती थी। उल्लेखनीय है कि 15 जून को गलवान घाटी में चीन की सेना ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। इसमें 20 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे।

देश में 5जी प्रौद्योगिकी का ढांचा बनाने में अहम भूमिका निभाएगी जियो : रिलायंस

आईपीटी नेटवर्क

नयी दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी वार्षिक रपट में कहा है कि देश में 5जी ढांचा बनाने में जियो की भूमिका अहम होगी। यह बात कंपनी ने बाजार के रुख को देखते हुए कही है। मोबाइल सेवाओं के लिए न्यूनतम आधार कीमत तय करने के मुद्दे पर कंपनी ने कहा दूरसंचार कंपनियों द्वारा दिसंबर में बढ़ाए गए शुल्क का असर हाल में दिखने लगा है। इससे बाजार स्थितियां बेहतर हुई हैं। रपट में कहा गया है कि सरकार ने भी 2020-21 के दौरान अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी की मंशा जतायी है। ऐसे में जियो के पास पहले से 5जी प्रौद्योगिकी के लिए तैयार प्रणाली और फाइबर परिसंपत्ति है। बाजार के रुख को देखा जाए तो देश में 5जी वातावरण के विकास में जियो की भूमिका अहम होगी। शेयरधारकों को भेजे पत्र में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि देश में अभी भी लाखों उपयोक्ता 2जी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे में देश को पूरी तरह 2जी से 4जी या उससे आगे की प्रौद्योगिकी में लाने की तत्काल जरूरत है, और इस बदलाव

के लिए जियो के पास कई अवसर हैं। उन्होंने कहा, ''पिछले दो साल से अधिक समय में 'जियोफोन' 10 करोड़ उपयोक्ताओं को 2जी से 4जी तक लाने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि जियो को देश के लिए 4जी प्रौद्योगिकी खड़ा करने में मिली सफलता ने फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया। अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो के उपयोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 31 मार्च 2020 तक इनकी संख्या 38.75 करोड़ पहुंच चुकी है। मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में क्रांति लाने के बाद जियो अब उपयोक्ताओं की संख्या और समायोजित सकल आय के हिसाब से देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है। उन्होंने कहा कि जियो अपनी अत्याधुनिक वायर प्रौद्योगिकी के माध्यम से घरों और प्रतिष्ठानों तक इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने का काम भी कर रही है। इससे एक ही मंच पर कई डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मजबूत बुनियाद तैयार करने में मदद मिलेगी। रपट के मुताबिक मार्च 2020 के अंत तक जियो फाइबर सेवा लेने वाले घरों की संख्या 10 लाख हो गयी। अंबानी ने कहा कि ई-वाणिज्य सेवाओं के माध्यम संगठित खुदरा कारोबार के लिए वृद्धि के और अवसर खुलेंगे। रिलायंस रिटेल और व्हाट्सएप ने रिलायंस रिटेल के डिजिटल कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक साझेदारी की है। इससे जियोमार्ट मंच का इस्तेमाल व्हाट्सएप पर किया जा सकेगा और व्हाट्सएप छोटे कारोबारियों को समर्थन दे सकेगी।

उड़ान योजना के तहत 16 सी-प्लेन मार्गों की पहचान

आईपीटी नेटवर्क

नयी दिल्ली। उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए 16 सी-प्लेन मार्गों की पहचान की गयी है। सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सी-प्लेन ऐसे विमानों को कहा जाता है जो पानी से उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम होते हैं। कुछ सी-प्लेन भूमि और पानी दोनों जगह से उड़ान भरने और लैंड कर सकते हैं। आधिकारिक बयान के मुताबिक इन 16 मार्ग में साबरमती और सरदार सरोवर का मार्ग भी शामिल है। यह मार्ग 'स्टैच्यू ऑफ युनिटी' को हवाई मार्ग से जोड़ेगा। इसके अक्टूबर 2020 तक परिचालन में आने की संभावना है।

केंद्रीय पोत-परिवहन राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने बैठक के दौरान सी-प्लेन परियोजनाओं की समीक्षा की। बयान के अनुसार अब तक क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने की उड़ान परियोजना के तहत ऐसे 16 मार्ग की पहवान की गयी है। इस तरह के विमानों से देश के पहाड़ी क्षेत्रों और अन्य दुर्गम इलाकों में हवाई यात्रा विकल्प मुहैया कराने में मदद मिलेगी। मंडाविया ने कहा कि साबरमती और सरदार सरोवर-नर्मदा मार्ग से पर्यटन बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह पर्यटकों को 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का विहंगम दृश्य उपलब्ध कराएगा। मंत्री ने अधिकारियों को अमेरिका, कनाडा, मालदीव और ऑस्ट्रेलिया के जल विमानपत्तनों का अध्ययन करने के बाद इसका एक भारतीय मॉडल विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं।

साथ ही सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण को भी साबरमती और सरदार सरोवर-नर्मदा मार्ग पर अक्टूबर 2020 तक परिचालन शुरू करने के लिए भी गठजोड़ करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण, देश के अंदरूनी जलमार्गों पर सी-प्लेन परियोजना का जबकि सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड तटीय जलमार्गों पर ऐसी परियोजनाओं काप्रबंधन देखेगी।

आईएमडी की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 43वें स्थान पर कायम, सिंगापुर अव्वल

नयी दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट (आईएमडी) तैयार किए जाने वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धा-क्षमता सूचकांक में इस साल भी 43वें स्थान पर बनी रही। आईएमडी की रपट के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां मसलन कमजोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम हैं। कुल 63 देशों की इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर बरकरार है। वहीं डेनमार्क दूसरे स्थान पर आ गया है। पिछले साल वह आठवें स्थान पर था। वहीं स्विट्जरलैंड एक स्थान चढ़कर तीसरे स्थान पर आ गया है। नीदरलैंड चौथे स्थान पर कायम है।

वहीं हांगकांग फिसलकर पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। 2019 में वह दूसरे स्थान पर था। वहीं अमेरिका भी फिसलकर तीसरे से दसवें स्थान पर पहुंच गया है। चीन भी 14वें से 20वें स्थान पर पहुंच गया है। ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) में भारत का स्थान चीन के बाद है। रूस 50वें, ब्राजील 56वें और दक्षिण अफ्रीका 59वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बिजनेस स्कूल द्वारा यह रैंकिंग 1989 से हर साल दी जा रही है। भारत इसमें लगातार 41वें स्थान पर रहा है। लेकिन 2017 में भारत प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में फिसलकर 45वें स्थान पर पहुंच गया था। 2018 में यह 44वें और 2019 में 43वें स्थान पर आ गया। आईएमडी ने कहा कि 2020 में भी भारत 43वें स्थान पर ही रहा है।

भारत कृषि व्यापार वर्ष 2020 के उत्तरार्द्ध में गति पकड़ सकता है: फिच साल्युशन्स

एजेंसी

नयी दिल्ली। विश्लेषक कंपनी फिच साल्युशन्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि देश के कृषि व्यापार के कैलेंडर वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में वापस गति पकड़ने की उम्मीद है।यह मार्च-जून में लॉजिस्टिक्स की समस्या मुद्दों के कारण कोविड -19 रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान बाधित हो गया था। केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए 25 मार्च से 30 अप्रैल तक सख्ती से राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन को लागू किया और फिर मई में आंशिक रुप से लॉकडाऊन को लागू किया था। रिपोर्ट में कहा गया है, ''इन उपायों में, आजीविका की सुरक्षा के लिए घरेलू स्तर पर कोविड-19 संक्रमण में निरंतर वृद्धि के बावजूद, आठ जून से विभिन्न चरणों में ढील दी गई।

हमें संज्ञान में लेना होगा कि कुछ राज्य मई से आगे भी लॉकडाउन की स्थिति में रहेंगे, जो अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवसाय परिचालन को बाधित करना जारी रखेगा।'' लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण लॉकडाउन के दौरान कृषि व्यापार बहुत बाधित हो गया था, यह बताते हुए फिच सॉल्यूशंस ने कहा कि मार्च-जून में निर्यात (चावल, चीनी) और आयात (पाम ऑयल) दोनों लड़खड़ा गए। इसमें कहा गया है, ''हम वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में जोरदार तरीके से वापस व्यार के गति पकड़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम वर्ष 2020 की पहली छमाही में दर्ज हुई गिरावट के कारण वर्ष 2020 का कुल व्यापार का आकार वर्ष 2019 के स्तर या उससे नीचे रहने का अनुमान लगाते हैं।''

मजदूरों की कमी - का एक आंशिक कारण यह भी है कि कई प्रवासी मजदूर आजीविका तलाशने के लिए अपने गांव घर लौट गये थे। इस मजदूरों की कमी की वजह से धान की रोपाई व बागवानी के काम में कुछ कठिनाई होने की संभावना है। रिपोर्ट में डेयरी और पशुधन उत्पादन क्षेत्र के पर्याप्त रूप से प्रभावित होने की बात करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि पशुधन का परिवहन प्रतिबंधित था या यह काम काफी जटिल हो गया था, जबकि मांस की दुकानें या बूचड़खाने बंद हो गए।

जिसके बारे में कुछ व्यापारिक कंपनियों ने कहा कि उन्हें 'आवश्यक सेवा' नहीं माना गया था। डेयरी क्षेत्र के संबंध में, फिच सॉल्यूशंस ने कहा कि फल और सब्जियों जैसे जल्दी खराब होने की संभावना वाले खाद्य वस्तुओं में कई बार कीमतों में काफी घट बढ़ देखी गई। लेकिन इसके विपरीत, पूरे भारत में उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति अपेक्षाकृत व्यवधानमुक्त रही है।

जेम मंच पर बिक्री के लिए 'उत्पाद का मूल देश' अंकित करना अनिवार्य

एजेंसी

नयी दिल्ली। 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को आगे बढ़ाते हुए सरकारी खरीद के ऑनलाइन पोर्टल 'गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने विक्रेताओं के लिए उत्पादों पर 'उत्पादन के मूल देश' का नाम अंकित करना अनिवार्य कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वहीं 'मेक इन इंडिया' पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उसने अपने मंच पर उत्पादों में 'स्थानीय मूल्यवर्द्धन' के योगदान के उल्लेख का प्रावधान भी किया है। पोर्टल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तल्लीन कुमार ने कहा, '' आत्मनिर्भर भारत के लिए जेम ने एक अहम कदम उठाया है। उसने विक्रेताओं के लिए नए उत्पाद पंजीकृत करने पर उसके 'उत्पादन के देश' (कंट्री ऑफ ओरिजिन) का अंकित करना अनिवार्य कर दिया है।'' उन्होंने कहा कि जो विक्रेता इस नियम में बदलाव से पहले अपने उत्पादों को मंच पर पंजीकृत कर चुके हैं उन्हें समय-समय पर याद दिलाया जाएगा कि वह उत्पादों के 'उत्पादन का देश' अंकित करें अन्यथा उनके उत्पाद को मंच से हटा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इन नए फीचरों में कंट्री ऑफ ऑरिजिन के साथ-साथ उत्पादों पर स्थानीय मूल्यवर्द्धन का प्रतिशत भी अंकित होगा। मंच पर 'मेक इन इंडिया' फिल्टर भी लगाया गया है जो खरीदारों को भारतीय उत्पादों के चयन में मदद करेगा। खरीदार चाहे तो केवल उन उत्पादों की खरीद कर सकता है जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत स्थानीय मूल्यवर्द्धन हो। कुमार ने कहा कि अपनी शुरुआत से ही जेम 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही देश के छोटे स्थानीय विक्रेताओं को सरकारी खरीद में प्रवेश करने की सुविधा दे रहा है। इस महीने की शुरुआत में सरकार ने सरकारी खरीद के नियमों को संशोधित किया था, जिसमें कहा गया था कि ऐसे उत्पादों एवं सेवाओं को वरीयता दी जाएगी जिनमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक स्थानीय मूल्यवर्द्धन शामिल है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत की अपनी पोजीशन, पीपीपी में तीसरे स्थान पर बरकरार

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत 2017 के क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना हुआ है। सरकार ने मंगलवार को विश्व बैंक के हवाले से यह कहा। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के स्तर पर रुपया प्रति डॉलर पीपीपी 2017 में बढ़कर 20.65 हो गया जो 2011 में 15.55 था।

वहीं रुपये के लिये डॉलर की विनिमय दर 2017 में बढ़कर 65.12 हो गई जो 2011 में 46.67 थी।साथ ही कीमत स्तर सूचकांक (पीएलआई) यानी पीपीपी का संबंधित बाजार विनिमय दर से अनुपात 2017 में सुधरकर 47.55 रहा जो 2011 में 42.99 था। इसका उपयोग अर्थव्यवस्थाओं में कीमत स्तर की तुलना करने में किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार वर्ष 2017 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा। पीपीपी के हिसाब से वैश्विक जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी 6.7 प्रतिशत रही (दुनिया के कुल 1,19,547 अरब डॉलर के जीडीपी में 8,051 अरब डॉलर) वहीं चीन और अमेरिकी हिस्सेदारी क्रमशः 16.4 प्रतिशत और 16.3 प्रतिशत है।

- 2017 के लिए नया पीपीपी

एनएसओ की विज्ञप्ति के मुताबिक पीपीपी आधारित वैश्विक वास्तविक व्यक्तिगत खपत में हिस्सेदारी और वैश्विक सकल पूंजी निर्माण के आधार पर भी भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक ने इंटरनेशनल कम्पैरिजन प्रोग्राम (आईसीपी) के तहत संदर्भ वर्ष 2017 के लिए नया पीपीपी जारी किया है। यह दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में जीवन स्तर की लागत में अंतर को समायोजित करता है।

वैश्विक स्तर पर आईसीपी में 176 देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (यूएनएससी) के तहत आईसीपी दुनिया की सबसे बड़ी आंकड़ा संग्रह पहल है। इसका मकसद पीपीपी का आकलन करना है जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों की तुलना के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने अपनी क्षेत्रीय स्थिति भी बरकरार रखी है और पीपीपी के संदर्भ में क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 20.83 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वह दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही। वहीं चीन 50.76 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पहले और इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर रही।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।